

हाईवे चैनल

□ वर्ष - 29 □ अंक - 168 □ रायपुर, शनिवार 11 जुलाई 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य - 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

एनजीटी का बड़ा फैसला

रायपुर समेत तीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर रोक

रायपुर 11 जुलाई (हाईवे चैनल)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जल संरक्षण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सहित देश के तीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

एन एनजीटी की अनुमति के बिना इन स्टेडियमों में किसी भी प्रकार का खेल आयोजन नहीं किया जा सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। एनजीटी के आदेश की जद में रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम आए हैं। अधिकरण ने कहा कि देश के कई हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में बड़े खेल परिसरों की जिम्मेदारी है कि वे भूजल के उपयोग, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) जैसी व्यवस्थाओं का प्रभावी पालन करें। अधिकरण के अनुसार, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और एनजीटी की ओर से संबंधित स्टेडियमों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके रायपुर, जयपुर और मुंबई के स्टेडियमों



ने निर्धारित समय में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। इसी को गंभीरता से लेते हुए एनजीटी ने अंतरिम प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि अप्रैल में एनजीटी ने देश के छह प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों से मैदान और पिचों के रखरखाव में उपयोग किए जा रहे पानी के स्रोत, भूजल दोहन और जल प्रबंधन प्रणाली की विस्तृत जानकारी मांगी थी।

इनमें नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, लखनऊ का इकाना स्टेडियम और कटक का बाराबती स्टेडियम भी शामिल थे। अरुण जेटली और इकाना स्टेडियम जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं, जबकि बाराबती स्टेडियम ने अतिरिक्त समय की मांग की है। अब इस मामले में 17 अगस्त की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

ब्रेकिंग न्यूज

बाल तस्कर एक और अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, चार बच्चों को बचाया, 10 आरोपी भी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11 जुलाई (न्यूज चैनल)। नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के एक और अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तस्कर, बिचौलिया, खरीदार और अस्पताल संचालक से लेकर असली माता-पिता तक शामिल हैं। मध्य जिला पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से चार और बच्चों को सुरक्षित बरामद भी किया है। इससे पहले, पुलिस ने 5 जून को एक और अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा कर नवजात समेत 5 बच्चों को मुक्त कराया था। गिरोह की पड़ताल के दौरान दूसरे गिरोह का पता चला। अब तक नौ बच्चों को इससे मुक्त कराया जा चुका है।



चूहा- बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने अचानक अपना नाम वापस ले लिया। चुहिया- हांजी, आखिर क्या करें, अभी तो भगवान राम भी साथ नहीं देने वाले...!

करंट से युवक की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, आधी रात को नेशनल हाईवे किया जाम

मुंगेली, 11 जुलाई (हाईवे चैनल)। आधी रात करंट लगने से एक युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। मृतक के परिजनों, स्थानीय नागरिकों एवं भाजपा नेता वेदप्रकाश के नेतृत्व में लोगों ने जरहागांव बस स्टैंड पर नेशनल हाईवे को करीब आधे घंटे तक जाम कर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टरों की नियुक्ति तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। जानकारी के अनुसार, नगर निवासी गोविन्द साहू उर्फ गोलू को बिजली का करंट लग गया था। घटना के तुरंत बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन परिजनों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उस समय अस्पताल में ड्यूटी पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। उनका कहना है कि अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने प्राथमिक उपचार के बजाय मरीज को तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आनन-फानन में परिजन गंभीर हालत में गोविन्द साहू को जिला अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। उनका आरोप है कि यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरहागांव में समय पर डॉक्टर उपलब्ध होते और तत्काल उपचार मिलता तो संभवतः



युवक की जान बचाई जा सकती थी। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजन, स्थानीय नागरिक तथा भाजपा नेता वेदप्रकाश नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि देर रात जरहा गांव बस स्टैंड पहुंचे और नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और यातायात करीब आधे घंटे तक प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में घटना के लिए जिम्मेदार डॉक्टर अथवा संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करना तथा मृतक के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता एवं मुआवजा प्रदान करना शामिल रहा।

सूचना मिलने पर संबंधित पुलिस अधिकारी तथा बल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री मोदी बोले-खुलेगा निवेश और व्यापार के नए द्वार

नई दिल्ली, 11 जुलाई (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गहराई और गति देगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से बाजार तक पहुंच, निवेश, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और प्रतिभाओं के आदान-प्रदान के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने यह बात न्यूजीलैंड में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों और चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान कही। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय



वार्ता में 18 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी शुरूआत को तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑकलैंड पहुंचे। करीब 40 वर्षों बाद किसी भारतीय

प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। यह दौरा हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए खज्र पर हस्ताक्षर के बाद हो रहा है।

व्यापार जगत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत आर्थिक साझेदारी से उद्योगों, नवाचारकर्ताओं और

युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, युवा कार्यबल, डिजिटल क्रांति और लगातार हो रहे आर्थिक सुधार न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए निवेश के बड़े अवसर उपलब्ध कराते हैं। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के निवेशकों को भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर, नागरिक उड्डयन, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी परिवहन, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने दोनों देशों के निजी क्षेत्र से स्टार्टअप, फिनटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने की भी अपील की।

बस्तर की जैविक खेती को मिलेगा वैश्विक बाजार यूरोप तक पहुंचेंगे जैविक उत्पाद: विजय शर्मा

एपीडा, कृषि एवं पंचायत विभाग के साथ बनी कार्ययोजना, बस्तर संभाग में होगा विशेष सर्वे और परीक्षण



रायपुर, 11 जुलाई (हाईवे चैनल)। बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बड़े बाजारों तक पहुंचाने तथा किसानों की आय में नारायणपुर और कांकर के नक्सल मुक्त हुए ग्रामों के अपने बस्तर प्रवास के दौरान अनेक किसानों ने उन्हें जानकारी दी थी कि उन्होंने अपने खेतों में कभी भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गांवों को चिन्हित कर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) से जोड़ा जाए, ताकि उनके उत्पादों का विधिवत जैविक प्रमाणन कराया जा सके और उन्हें देश के बड़े बाजारों के साथ-साथ यूरोप सहित अन्य विदेशों

प्राकृतिक धरोहर हैं और इनकी जैविक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने वर्तमान मूल्य की तुलना में तीन से चार गुना अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बस्तर की विशिष्ट कृषि पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। बैठक में बस्तर के जैविक उत्पादों को यूरोप सहित अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी), सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।

बाजारों तक पहुंचाया जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि जैविक प्रमाणन के बाद बस्तर के किसानों को उनके उत्पादों का वर्तमान मूल्य की तुलना में तीन से चार गुना अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बस्तर की विशिष्ट कृषि पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। बैठक में बस्तर के जैविक उत्पादों को यूरोप सहित अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी), सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने जारी की महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त

66 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डीबीटी से 626.25 करोड़ रुपये अंतरित



रायपुर, 11 जुलाई (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री

विष्णुदेव साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर

बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प की पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

बेटे से मिलते ही मां की आंखों से छलके आंसू, 4 साल बाद सुरक्षित घर लौटा पप्पू- इकराम अहमद

बिरगांव, 11 जुलाई (हाईवे चैनल)। बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 25 की निवासी श्रीमती मधु ध्रुव के लिए वह पल बड़ेहद भावुक रहा, जब उनका लापता बेटा पप्पू (पिता स्वर्गीय हाजारी ध्रुव) लगभग चार वर्षों बाद मुरादाबाद अस्पताल में होने की जानकारी मिली,मिलने पहुंची,बेटे को सामने देखकर मां अपने आंसू नहीं रोक पाई। एमआईसी सदस्य एवं प्रभारी लोक निर्माण विभाग इकराम अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि पप्पू वर्ष 2022 से लापता था। दिनांक 07 जुलाई 2026 की सुबह मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) रेलवे पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया है, जिसे जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया है। उक्त भगवान राम किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है।



निगम क्षेत्र के विभिन्न व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से तत्काल खोजबीन प्रारंभ की गई। प्रयासों के फलस्वरूप युवक की मां एवं परिजनों का पता चल सका। इसके पश्चात बिरगांव नगर निगम के महापौर नंदलाल देवांगन को मामले की जानकारी दी गई। महापौर के सहयोग से तत्काल प्राइवेट एम्बुलेंस से परिजनों को तत्काल मुरादाबाद (उ.प्र.) भेजा गया, जहां उन्होंने युवक की पहचान कर उसे अपने साथ सुरक्षित सकुशल बिरगांव, पप्पू अपनी मां के साथ बिरगांव रायपुर पहुंच गया है।

राम मंदिर चंदा और चढ़ावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राम मंदिर ट्रस्ट की सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग

रायपुर, 11 जुलाई (हाईवे चैनल)। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस कार्यसमिति छद्म के मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की उपस्थिति में पत्रकारिता की संबंधित करते हुये कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं। देश के कोने-कोने से गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई, अपने गहने, अपनी बचत और अपनी श्रद्धा लेकर राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आए। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने लगभग तीन दशकों तक भगवान राम के नाम



पर राजनीति की, देश के गरीब व मध्यम वर्ग से राम के नाम पर चंदा एकत्र किया और इसी आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त की।

आज वही करोड़ों रामभक्त यह पूछने को मजबूर हैं कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया? यह केवल आर्थिक चोचाला नहीं है। यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ किया गया चोर विश्वासघात है।

तीन बड़े सवाल

1. जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा?
2. अगर सब कुछ ठीक था, तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए?
3. अगर कुछ गलत नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है?

कांग्रेस पार्टी की मांगें

▶ **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने जवाब दें:** प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि ट्रस्ट के गठन, शीर्ष नियुक्तियों और प्रशासनिक निगरानी में उनकी सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका रही है और इतने गंभीर आरोपों के बाद वे अब तक मौन क्यों हैं।

▶ **तत्काल गिरफ्तारी:** चंपत राय, अनिल मिश्रा और इस पूरे घोटेले में शामिल सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए।

▶ **सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच:** पूरे प्रकरण की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस

कथित लूट के पीछे कौन लोग हैं और किसके संरक्षण में यह सब वर्षों तक चलता रहा।

▶ **श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए:** वर्तमान ट्रस्ट को भंग कर धर्माचार्यों, प्रतिष्ठित नागरिकों, प्रशासनिक विशेषज्ञों और स्वतंत्र सदस्यों के साथ एक नया, पारदर्शी और जवाबदेह ट्रस्ट गठित किया जाए।

▶ **चढ़ावे और चंदे का पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट:** राम मंदिर के लिए प्राप्त समस्त चंदे, चढ़ावे, भूमि खरीद, आयोजनों और व्ययों का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। भगवान राम किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है।